डेरी बोर्ड के प्रयासों से झारखंड के ग्रामीण दूध उत्पादकों के जीवनयापन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है । आरंभ हुई नई दूध संकलन प्रक्रियाओं के कारण अब उत्पादक अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं । सहकारी सदस्यों के वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं । जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोलने के लिए दूध उत्पादकों प्रोत्साहित किया जा रहा है । कई उत्पादकों को ने इस योजना के अंतर्गत अथवा अन्य प्रकार से पहले ही बैंक खाते खोल लिए हैं । वर्तमान में 100% दूध उत्पादक सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त कर रहे हैं ।

परामर्श सेवाएं: दूध संकलन, प्रसंस्करण एवं विपणन के अलावा, जेएमएफ ने विभिन्न इनपुट गतिविधियों जैसे कि पीई शिविर, टीकाकरण, पशु उपचार, पशु आहार, खनिज मिश्रण इत्यादि के जरिए डेरी पशुओं की उत्पादकता वृद्धि संबंधी विभिन्न पहल की शुरूआत भी की है । उत्पादकता वृद्धि सेवाओं के अंतर्गत 33144 पशु तथा 5 हजार से अधिक दूध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं ।

604 उत्पादकता वृद्धि शिविर आयोजित किए गए । 382 गांवों में पशु उपचार शिविर आयोजित किए गए और 18,407 टीकाकरण किए गए। 565 दूध पूलिंग प्वाइंटों पर 3,199 मी.टन पशु आहार की बिक्री की गई । 9 मी.टन पशु चारा और 1 मी.टन खनिज मिश्रण की बिक्री की गई/वितरित किया गया ।

देशी नस्लें: देशी गाय की नस्लों जैसे राठी (राजस्थान) और गिर (गुजरात) के संवर्धन हेतु होटवार में एक देशी पशु फार्म की स्थापना की गई है। प्रदर्शन हेतु बारहमासी एवं मौसमी दोनों प्रकार के हरे चारे की खेती के लिए एक आधुनिक चारा प्रदर्शन फार्म का विकास किया गया है ।

एनडीपी: अब, एनडीपी चरण-। में झारखंड को शामिल किया गया है । एनडीडीबी की राष्ट्रीय डेरी योजना । के अंतर्गत झारखंड दूध संघ द्वारा 2 उप-परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें कुल अनुदान सहायता राशि ₹4.91 करोड़ शामिल है। एनडीपी-। के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों में शामिल हैं - कम लागत पर स्थानीय उपलब्ध आहार संसाधनों के इस्तेमाल द्वारा दुधारू पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय जानकार व्यक्तियों (एलआरपी) के माध्यम से आहार संतुलन की उप-परियोजनाएं; गांव आधारित दूध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) उप-परियोजनाएं दूध उत्पादकों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी दूध संकलन प्रणाली उपलब्ध कराएंगी ।

अन्य पहल:

फलों और सब्जियों के लिए बाजार की पहुंच: एमडीएफवीएल, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने झारखंड के मटर उत्पादक किसानों को एक फ्रोजन लाईन के जरिए बाजार की पहुंच उपलब्ध कराके अल्प विकसित क्षेत्रों तक किसानों के संपर्क में विस्तार किया है । इस सुविधा से रांची और उसके आस-पास के क्षेत्रों में उत्पादित कटी सब्जियों का प्रसंस्करण भी संभव हो सकेगा। चरण-। के अंतर्गत, इस कंपनी ने 4,350 मी.टन की एक नई आधुनिक आईक्यूएफ प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना की है और रांची में 17,700 मी.टन की पल्प प्रोसेसिंग सुविधा स्थापित करने की इसकी आगामी योजना है । दूसरा चरण इस क्षेत्र के टमाटर उत्पादकों तथा आम एवं अन्य फलों के उत्पादकों को सुरक्षित बाजार की पहुंच उपलब्ध कराने में सहायक होगा ।

दूध के माध्यम से बाल विकास में सहयोग: एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन (एनएफएन) सुरक्षित दूध एवं दूध उत्पादों को उपलब्ध कराकर स्कूलों के बच्चों में कुपोषण के उन्मूलन के लिए निरंतर योगदान दे रहा है। एनएफएन का गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम एनडीडीबी की सहायक कंपनियों एवं पीएसयू से उनके कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रतिबद्धताओं के तहत दान एकत्रित करके स्कूलों के बच्चों को सभी कार्य दिवसों में नि:शुल्क फोर्टिफाइड पास्चुराइज्ड/स्टरलाइज्ड फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराता है । 2017 में लातेहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एनएफएन के गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी । वर्तमान में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड में 43 स्कूलों के 18,000 से अधिक विद्यार्थियों को फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है ।
झारखंड सरकार की कान्हा योजना के अंतर्गत, जेएमएफ को गिफ्ट मिल्क पहल की शुरूआत करने और लातेहार, रांची, गुमला, हजारीबाग, सिमदेगा, खुंटी, लोहारदगा और रामगढ़ में लगभग 1 लाख बच्चों को शामिल करने का उत्तरदायित्व दिया गया है । भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी 2019 को हजारीबाग में इस योजना का शुभारंभ किया । उसके बाद से रांची, लातेहार और हजारीबाग के स्कूलों के बच्चे इस योजना के अंतर्गत दूध प्राप्त कर रहे है ।